

स.प्र.वि./प्रम्बाला/103-85/35032.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं (1) आफिसर इन्चार्ज, सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़, (2) सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट रिसर्च फार्म, मन्सा देवी, पो. आ. मणिमाजरा, जिला अम्बाला, के श्रमिक श्री रामा कान्त तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने के लिए निर्दिष्ट करने हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामलें हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामलें हैं :—

क्या श्री रामा कान्त की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

जे० पी० जैन, उप-सचिव ।

दिनांक 29 अगस्त, 1985

स.प्र.वि./एफ.बी./104-85/35255.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) नर्स, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) नर्स जे.सू.स. प्रवेश (नर्स) स्थापना अनुमति, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, सैक्टर 17, चण्डीगढ़, के श्रमिक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद के नीचे निर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामलें हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामलें हैं/हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक श्री राजपाल सिंह निनयोरटी की अनुसार यू.डी.सी. के पद पर दिनांक 11 मई, 1982, से पत्रोन्नति का हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?

स.प्र.वि./एफ.बी./116-84/35277.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं आइंशर गुडअर्थ लि०, 59, औद्योगिक भवन, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामलें हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामलें हैं/हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

- (1) क्या संस्था का स्टाफ कम से कम 300 रुपये प्रति मास मंहगाई भत्ता जोकि अग्रिम आर्थिक विविग इंडेक्स नम्बर 1960 पर 2 रुपये प्रति बिन्दु के हिसाब में आधारित हो लेने का हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?
- (2) क्या संस्था को श्रमिक नियमित ग्रेड व स्केल पाने के हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?
- (3) क्या संस्था को ऐसे श्रमिक जिन पर ई.एस. आई. लागू नहीं होता वे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के इलाज पर दवाईयां खरीदने के लिए खर्ची गई राशि की अदायगी के हकदार है? यदि हां, तो किस विवरण में?
- (4) क्या संस्था में प्रचलित एल.टी.ए. की स्कीम का पुनर्गठन करना और इसमें 20 प्रतिशत वृद्धि करने में कोई औचित्य है? यदि हां, तो किस विवरण में?
- (5) क्या संस्था के श्रमिकों की रिटायरमेंट की आयु 58 साल तक करना उचित है? यदि हां, तो किस विवरण में?